भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-478
दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ऊर्जा दक्षता केंद्र

478. श्री श्रीरंग आप्पा चंद्र बारणेः
श्री अनिल यशवंत देसाईः
श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्रीमती भारती पारधीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों को संरेखित करके सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक हब में शामिल होने वाले देशों के नाम क्या हैं:

(ग) उक्त हब में शामिल होने के बाद देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि विकसित देशों की तुलना में अल्पविकसित देशों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए कितना व्यय करना होगा;

(ङ) क्या सरकार के अलावा अन्य निजी कंपनियों को भी इस प्रयास में शामिल करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भारत की ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में योगदान करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी हाँ, भारत ने वर्ष 2015 में अपने पहले प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के संबंध में लक्ष्यों को काफी पहले ही हासिल कर लिया था। इसके बाद, भारत ने वर्ष 2021 में सीओपी 26 में अपने एनडीसी को अपडेट किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना है। प्रौद्योगिकी अंतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना।

अक्टूबर 2024 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता कुल संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता का लगभग 46.2% है। भारत का अद्यतन एनडीसी कम कार्बन उत्सर्जन मार्ग की दिशा में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है, साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है।

(ख) : जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 को भारत को ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने का अनुमोदन दे दिया है।

अक्टूबर 2024 तक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे 16 देश हब में शामिल हो चुके हैं।

(ग): ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के बाद देश को मिलने वाले लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विश्व स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित नवीन ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और अवधारणाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सीखना।
(ii) ऊर्जा दक्षता में भारत के योगदान को प्रदर्शित करना तथा नेतृत्व का प्रदर्शन करना।
(iii) उद्योग, भवन और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा-कुशल समाधानों की तैनाती में तेजी लाना।
(iv) ऊर्जा दक्षता में नवीनतम अनुसंधान और विकास तक पहुंच को सुगम बनाना।

(घ) और (ङ) : भारत बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के ढांचे के भीतर सुरक्षा क्षेत्र (जिसमें ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है) में क्षेत्रीय सहयोग के लिए अग्रणी है, जिसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। ऊर्जा सहयोग से संबंधित अनुसंधान, संयुक्त परियोजनाएं, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि चलाने के लिए भारत में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(च) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने की दिशा में कई पहल की हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के भारत के प्रयासों में सहायक हैं।

इस संबंध में प्रमुख पहलों में कुशल उपकरणों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, टिकाऊ भवन निर्माण के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन और सतत संहिता, बड़े उद्योगों में दक्षता के लिए प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार कार्यक्रम, परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) और भारतीय कार्बन बाजार शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023 तक, विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप वार्षिक CO_2 उत्सर्जन में 306 मिलियन टन की कमी आई है।

****